

**उ०प्र० के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री ने क्षेत्रीय
कृषि सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) का शुभारम्भ किया**

**यह सम्मेलन एक व्याहारिक दृष्टिकोण स्थापित कर रहा, देश के अलग-अलग क्षेत्रों
के एग्रोक्लाइमेटिक जोन व भौगोलिक तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि
क्षेत्र के लिये लक्ष्य तय करना अत्यन्त आवश्यक : मुख्यमंत्री**

**हमारे अन्नदाता किसान मेहनती, उन्हें शासन की योजनाओं के
बारे में जागरूक करने के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे**

**कृषि विज्ञान केन्द्रों ने प्रदेश के सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सेन्टर
ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बहुत कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया**

उ०प्र० में कृषि विकास की दर ०८ प्रतिशत से बढ़कर १८ प्रतिशत पहुंची

**प्रदेश सरकार ने कृषि को वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने की पहल मजबूती से आगे बढ़ाई
प्रधानमंत्री जी ने उ०प्र० में अलग-अलग प्रोडक्ट के कुछ इण्टरनेशनल सेण्टर उपलब्ध कराए,
वाराणसी में इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेण्टर बेहतर
परिणाम दे रहा**

प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर १०० कुन्तल तक पहुंचा

**आज किसानों के जागरूक होने के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा, कई
लाख हेक्टेयर खेती में किसानों ने अतिरिक्त फसल लेना प्रारम्भ किया**

**उ०प्र० में ४२५ लाख मीट्रिक टन गेहूं, २११ लाख मीट्रिक टन धान, २४५ लाख मीट्रिक टन
आलू का उत्पादन हो रहा, दलहन और तिलहन के उत्पादन में उ०प्र० ने प्रगति की**

सब्जी, अलसी, जौ, बाजरा के उत्पादन में प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई

**उ०प्र० के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास और जन कल्याण का एक नया
इतिहास रचा, आज उ०प्र० अनेक क्षेत्रों में देश में नम्बर वन राज्य : केन्द्रीय कृषि मंत्री**

माटी, जलवायु और मेहनती किसान उ०प्र० की शोभा बढ़ा रहे

लखनऊ : २४ अप्रैल, २०२६

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन को गति प्रदान कर अन्नदाता किसान की आय में वृद्धि हेतु ०९ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषक उत्पादक संगठन एवं प्रगतिशील किसानों के महासंगम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन एक व्याहारिक दृष्टिकोण स्थापित कर रहा है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों के एग्रोक्लाइमेटिक जोन व भौगोलिक तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिये लक्ष्य तय करना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिये व्यापक रोडमैप तैयार करने सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत वर्ष 'विकसित कृषि अभियान' और 'खेती की बात खेत में' कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों में किसानों का उत्साह तथा कृषि वैज्ञानिकों व कृषि शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षुओं के मन में बेहतरीन जिज्ञासा देखने को मिली। इस दौरान किसानों को पहली बार इनोवेशन को व्यावहारिक धरातल पर उतारने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ। लैब को लैण्ड तक पहुँचाने का अभिनव प्रयास पहली बार हुआ है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस अभियान को देश के धरातल पर व्यावहारिक रूप से उतारने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, केवल पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। जब यह पहल भारत सरकार के स्तर पर होती है, तो राज्य उसे स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। पहले यह अक्सर होता था कि नीतियां बनती थीं, लेकिन सभी कार्यक्रम औपचारिक आयोजन बनकर सम्पन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान मेहनती हैं तथा उन्हें व्यावहारिक जानकारी है। शासन की योजनाओं के बारे में अन्नदाता किसानों को अवगत कराने के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 69 कृषि विज्ञान केन्द्र थे। ज्यादातर कृषि विज्ञान केन्द्र बन्दी के कगार पर थे। आज प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में इनोवेशन हो रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों ने प्रदेश के सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बहुत कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया है। इनसे जुड़े वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र में डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फिर खेत में जाकर उस डेमोंस्ट्रेशन को दिखाते हैं। लगातार गोष्ठियां चलती हैं। किसानों से साथ लगातार संवाद स्थापित करते हैं। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 08 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पहुंच गयी है। हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का योगदान लगभग 41 से 42 प्रतिशत था। कृषि का योगदान लगातार कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर समन्वय हो, तो विकास तेजी से होता है। हमारे यहां अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान अभी भी 15 से 16 प्रतिशत है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का

योगदान 41 से 42 प्रतिशत से घटकर 20 से 21 प्रतिशत हो गया। प्रदेश सरकार ने इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने की पहल को मजबूती से आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज के समय में तकनीक बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग प्रोडक्ट के कुछ इण्टरनेशनल सेण्टर उपलब्ध कराए हैं। वाराणसी में इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेण्टर बेहतर परिणाम दे रहा है। इस संस्थान ने चावल की कई नई प्रजातियां दी हैं। प्रदेश के अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन में कौन सी प्रजाति प्रभावी हो सकती है और कौन सी तकनीक अपनाई जानी है, तकनीक का क्या प्रभाव हो सकता है, समय पर बुआई का उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, और क्वालिटी सीड उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकता है, यह सारे परिणाम हमें देखने को मिले हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 100 कुन्तल तक पहुंचा है, जो पहले 50 से 60 कुन्तल तक सीमित था। अल-नीनो के नाते गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। औद्यानिकी में आम की फसल को भी इसने प्रभावित किया है। हमें लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाना है। अच्छा सीड समय पर उपलब्ध कराना है। केमिकल फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टिसाइड की खपत को कम करते हुए नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना है। विकसित कृषि अभियान के अन्तर्गत गत वर्ष बाराबंकी निवासी प्रगतिशील किसान पद्म श्री रामसरन वर्मा के खेत में जाने का अवसर मिला था। इनके खेत में पूरी तरह व्यवहारिक चीजें देखने को मिलती हैं। रामसरन जी ने वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार की पहल के परिणामस्वरूप, प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पहले वर्ष में एक फसल होती थी, वहां तीन-तीन फसलें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यन्त उर्वरा है। यहां 85 से 86 प्रतिशत भूमि सिंचित है। यहां बेहतरीन कनेक्टिविटी है। प्रदेश सरकार किसानों के खेतों में 10 से 12 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। यह स्थितियां हमारे लिए बेहतरीन अवसर हैं। पहले किसानों को कोई जानकारी देने वाला नहीं था। आज किसानों के जागरूक होने के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। कई लाख हेक्टेयर खेती में किसानों ने अतिरिक्त फसल लेना प्रारम्भ किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, एटा आदि जनपदों में जाने का अवसर मिला। किसानों ने बताया कि पहले हम लोग एक फसल लेते थे, लेकिन अब तीन-तीन फसलें उगा रहे हैं। मई-जून में मक्का की फसल तैयार हो गई है, जिससे एक लाख रुपये प्रति एकड़ मुनाफा कमा रहे हैं। उन क्षेत्रों में किसानों की यह

अतिरिक्त आय है। यह तभी सम्भव हो पाया, जब प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर सीड उपलब्ध कराया। किसानों को प्रगतिशील खेती के बारे में जागरूक किया। किसानों के लिए प्रोक्योरमेण्ट सेण्टर स्थापित किए गए। आज उनको अच्छा दाम मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज अकेले उत्तर प्रदेश में 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 211 लाख मीट्रिक टन धान, 245 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हो रहा है। दलहन और तिलहन के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 48 लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार सब्जी, अलसी, जौ, बाजरा के उत्पादन में भी प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने आगरा के लिए इण्टरनेशनल पोटैटो सेण्टर स्वीकृत किया है, जो शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। सेण्ट्रल यू0पी0 का पूरा क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसान यहां दो फसलों के साथ आलू का अच्छा उत्पादन करता है। उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि डिमाण्ड के अनुसार मांग की आपूर्ति में अन्नदाता किसान सहभागी बन सके। इण्टरनेशनल पोटैटो सेण्टर से सेण्ट्रल यू0पी0 के जनपदों में फूड प्रोसेसिंग की अनेक यूनिट लगनी प्रारम्भ हो गयी हैं। इन प्रयासों से अब किसान को उनके उत्पाद का बेहतरीन दाम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मिलना प्रारम्भ होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर से सम्बन्धित क्षेत्रीय सम्मेलन अलग-अलग जोन में आयोजित करना तथा उसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री व कृषि सम्बन्धी अधिकारियों का सम्मिलित होना एक अच्छी पहल है। पहले यह सम्मेलन दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में होता था। अब अलग-अलग जोन में उस जोन से जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुरूप मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। साथ ही, उत्तर प्रदेश या इस जोन में पड़ने वाले उत्तर भारत के राज्य अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। स्वाभाविक रूप से सभी के अनुभवों का लाभ एक-दूसरे को होगा। इस पहल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संगोष्ठी के माध्यम से निकलने वाला अमृत अन्नदाता किसानों के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा है। आज उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में देश में नम्बर वन राज्य है। यह दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है। पहली जयपुर में हुई थी। यह कॉन्फ्रेंस हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है। एक तरफ यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हरित क्रांति की शुरुआत

इन्हीं राज्यों से हुई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में नम्बर एक पर है। यहां की माटी, जलवायु और मेहनती किसान इस राज्य की शोभा बढ़ाते हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य का कृषि रोड मैप बनना चाहिये, क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान का भला नहीं कर पाएंगे। देश में फार्मर आई0डी0 बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फार्मर आई0डी0 किसान की अलग पहचान बनाती है। इस आई0डी0 के माध्यम से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर व श्री भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्यमंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख, हिमाचल प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन मंत्री श्री जाविद अहमद डार, पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिडयां, पंजाब के उद्यान मंत्री श्री मोहिन्दर भगत एवं उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

PN-CM-North Zone Agriculture Conference-24 April, 2026